IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty

उत्तराखण्ड शासन

एकीकृत आजीविका संवाद

अंक 2 जनवरी 2015

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति– एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

परियोजना का साथ: सहकारिता की डोर महिलाओं के हाथ

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना वर्ष 2013-14 से राज्य के 8 जनपदों में कार्य कर रही है। परियोजना के अंतर्गत 71 सहकारितायें कार्य कर रही हैं। इन सभी सहकारिताओं को महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन सहकारिताओं से लगभग 33,605 शेयर धारक जुड़ चुके हैं जिसमें से 30,999 महिलायें हैं जो कुल शेयर धारकों का लगभग 93 प्रतिशत हैं। सहकारिताओं के बोर्ड में महिलाओं की संख्या 98 प्रतिशत है जो सतत् फैडरेशनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इन सहकारिताओं के 1012 शेयरहोल्डरों को पंचायती राज संस्थाओं के अगुवाओं के रूप में चुना गया है जिनमें से 770 वार्ड के सदस्य, 185 ग्राम प्रधान, 53 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 41 जिला पंचायतों के सदस्य हैं।

सभी महिला सदस्यों द्वारा सामाजिक कार्यों से अधिक व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत इन सहकारिताओं ने अब तक ₹ 8.37 करोड़ का व्यापार किया है जिससे लगभग 34,015 परिवार लाभान्वित हुये हैं। इन महिलाओं के द्वारा सहकारिताओं के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी प्रारंभ कर दी गयी हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनपद अल्मोड़ा में सहकारिताओं द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से टेक होम राशन का कार्य कर आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार उपलब्ध करवाया गया जो एक अच्छी पहल है। सहकारिताओं द्वारा इस कार्य से 1 करोड़ 11 लाख का व्यवसाय करके आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में एक अच्छी मिसाल कायम की गई है।

राज्य की गौरवशाली नन्दादेवी राजजात यात्रा में होमकुंड सहकारिता, चमोली द्वारा यात्रा के विभिन्न पड़ावों में टैंट स्थापित करके श्रद्धालुओं को टैंट हाउस में रहने की सुविधा प्रदान की गई। राज्य सरकार के साथ मिलकर उक्त सहकारिता ने इस यात्रा के संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा मार्ग में टैंट हाउस लगाकर सहकारिता के सदस्य ₹18,39,000.00 के व्यवसाय से लाभान्वित हुये। राजजात यात्रा के समापन पर होमकुंड सहकारिता की सदस्यों ने जिला प्रशासन के अनुरोध पर, 4 यात्रा पड़ावों से 2 ट्रक प्लास्टिक का कचरा उठाकर निस्तारण हेतु सुलभ इंटरनेशनल संस्था को हस्तांतरित किया और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भविष्य में भी सहकारितायें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर इसी प्रकार से कार्य करने के लिये प्रयासरत हैं। परियोजना द्वारा विभिन्न संस्थाओं, समूहों व अन्य गतिविधियों में महिलाओं की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करते हुये विभिन्न गतिविधियों द्वारा लाभान्वित किया जाना है। महिला सदस्यों द्वारा किये गये सभी कार्य उनके सशक्तीकरण, उनकी प्रतिभागिता, महिला नेतृत्व व आर्थिक साझेदारी के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

हम होंगे कामयाब ....

व्यावसायिक प्रशिक्षण, UGVS द्वारा क्रियान्वित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि घटक का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत 11 ट्रेडों का प्रशिक्षण परियोजना के 6 कौशल प्रदाता सहभागियों द्वारा दिया जा रहा है। दिसंबर 2014 तक इस कार्य हेतु 760 में से 681 अभ्यर्थियों को प्रवेश, 452 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं 233 अभ्यर्थियों को जॉब प्लेसमेंट दिलाया जा चुका है। इसी क्रम में 134 छात्र-छात्राओं द्वारा रोजगार प्राप्त किया गया। जनपद अल्मोड़ा की ललिता नेगी नाम की लड़की को परियोजना द्वारा कौशल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से खाद्य एवं पेय सेवा (F&B) में प्रशिक्षण देकर कैफे कॉफी डे में नौकरी दी गयी है जिसकी कहानी संक्षेप में कुछ इस प्रकार से है:-

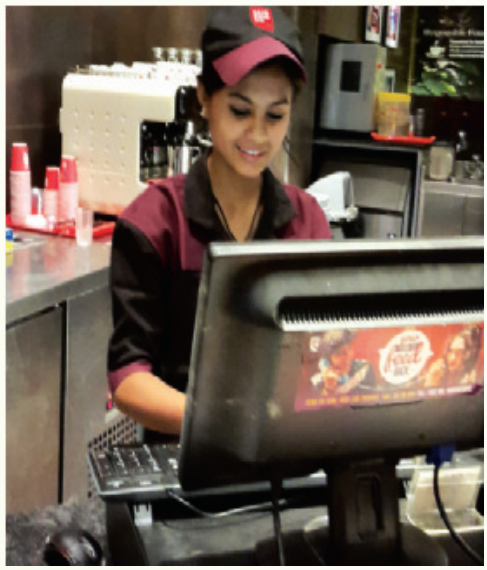

ललिता, छोटे कद की एक सुंदर 21 वर्षीय, बारहवीं पास लड़की है जिसका गांव तड़ियाल बाखली, चौखुटिया, उत्तराखंड में है। पिता की मृत्यु के बाद घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण वह अपनी माता को आर्थिक सहयोग देने के लिये नौकरी करना चाहती थी परंतु उसे मालूम नहीं था कि उसे करना क्या चाहिये? तभी उसे एक जागरूकता अभियान के माध्यम से UGVS के प्लेसमेंट लिंक्ड प्रशिक्षण के विषय में जानकारी हुई जिसको वह IL&FS (कौशल विकास निगम लिमिटेड) की सहभागिता से संचालित कर रहा था। वह उस स्थान पर गई जहां पर प्रेरक दल द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा था। उसने खाद्य एवं पेय सेवा (F&B) के लिये एंट्री गेट मूल्यांकन में प्रतिभाग किया और इसमें सफल रहने पर उसको प्रशिक्षण हेतु चुन लिया गया।

19 अगस्त 2014 को वह अपने एक माह के व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिये देहरादून पहुंची। सितम्बर माह में ललिता ने सफलता पूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंश के रूप में, ललिता को कैफे कॉफी डे में जॉब प्लेसमेंट के लिये साक्षात्कार में भाग लेने के लिये बुलाया गया। साक्षात्कार में सफल रहने पर उसे देहरादून स्थित कैफे कॉफी डे में ₹ 4700/- के वेतन पर नौकरी दे दी गई। अपने कार्य के साथ वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर रही है। अपनी नौकरी से वह प्रसन्न है तथा अपनी इस सफलता के लिये UGVS एवं IL&FS को हार्दिक धन्यवाद देती है।

शिक्षा की सीढ़ी चढ़े हर पीढ़ी

UGVS के अंतर्गत वर्ष 2008 में गठित एकता स्वायत्त सहकारिता दन्या, अल्मोड़ा को वर्तमान में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना तकनीकी व वित्तीय सहयोग दे रही है। सहकारिता के सदस्यों द्वारा इस दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा के स्तर की न्यूनता को देखकर परियोजना के गांव मलाण में एक प्राइमरी विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। कई प्रकार की चुनौतियों के कारण यह कार्य इतना आसान नहीं था।

सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों से जब इस बात की चर्चा की गई तो उन्होंने न केवल इस कार्य के लिये अपनी सहमति दी बल्कि स्कूल खोलने के लिये एक भवन और पंचायत निधि से ₹ 30,000 की धनराशि भी प्रदान की। वर्ष 2014-15 में एकता पब्लिक स्कूल, मलाण शिक्षण कार्य हेतु तैयार हो गया। सहकारिता ने स्कूल के लिये कुछ आवश्यक सामान जैसे दरियां, किताबें, मेज कुर्सी आदि खरीदने के लिये वित्तीय सहायता दी। इसके अतिरिक्त सहकारिता स्कूल को प्रतिमाह ₹ 2,000 की वित्तीय सहायता देती है। वर्तमान में बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से प्रतिमाह मात्र ₹ 200.00 की फीस ली जाती है। वर्ष 2014 के अगस्त माह तक इस स्कूल में 30 छात्र प्रवेश ले चुके हैं। सहकारिता अपने मजबूत इरादों के कारण इस स्कूल का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।

बेमौसमी सब्जी उत्पादन : आजीविका का संसाधन

जनपद बागेश्वर की निर्मल स्वायत्त सहकारिता की ग्राम गुरना की लाभार्थी श्रीमती इन्द्रा देवी, संघे शक्ति स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। इनके पति की वार्षिक आय लगभग ₹ 40,000 है। इन्द्रा देवी के पास 20 नाली भूमि है जिसमें 8 नाली सिंचित व 12 नाली भूमि असिंचित है।

इन्द्रा देवी ने परियोजना के माध्यम से संरक्षित वातावरण में (पॉलीहाउस में) बेमौसमी सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। परियोजना द्वारा इस क्षेत्र में कुल 6 पॉलीहाउस लगाये गये थे। वर्ष 2011-12 में इन्द्रा देवी ने भी एक पॉलीहाउस लगाया जिसमें उन्होंने परियोजना के सहयोग से बेमौसमी सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूलगोभी, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च आदि की नरसरी तैयार कर इनका व्यावसायिक उत्पादन करना प्रारंभ किया। इन सब्जियों को बेचकर श्रीमती इन्द्रा देवी को पिछले 5 वर्षों में कुल लागत ₹ 3,930 के सापेक्ष कुल मिलाकर ₹ 15,660 (वर्ष 2009- ₹ 3,000, वर्ष 2010 - ₹ 3,250, वर्ष 2011 - ₹ 3,950, वर्ष 2012 - ₹ 3700 और वर्ष 2013-14 में ₹ 1760) की आय प्राप्त हुई। उनके द्वारा इस गतिविधि को करने से गांव के लोगों में बेमौसमी सब्जियों के व्यावसायिक उत्पादन के प्रति रूझान बढ़ने लगा है। सभी सदस्य केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि स्थानीय बाजार को भी ताजी सब्जी उपलब्ध करवा रहे हैं। सब्जी उत्पादन गतिविधि से इंद्रा देवी की आर्थिक स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है।

कृत्रिम गर्भाधान: पशुओं की नस्ल सुधार के लिये वरदान

पर्वतीय कृषि विपणन स्वायत्त सहकारिता, घिंघराण, दशोली, चमोली के नैल-मलाना गाँव के समूह के सदस्य श्री दर्शन सिंह वर्ष 2008 में UGVS के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े। परियोजना के कार्यकर्ताओं ने दर्शन सिंह की रूचि को देखते हुए उनको पशु पैरावेट बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। इनको परियोजना द्वारा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा सहायतित पशुलोक सेवा केन्द्र, ऋषिकेश से 4 माह का प्रशिक्षण दिया गया जिसके अंतर्गत इनको गाय-भैसों में कृत्रिम गर्भाधान, पशु टीकाकरण, पशुओं में होने वाले रोग तथा पशुओं को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।

वर्ष 2009-2010 में परियोजना द्वारा पशुलोक सेवा केन्द्र के माध्यम से इनको एक पैरावेट सेन्टर उपलब्ध करवाकर केंद्र संचालन हेतु आवश्यक चीजें जैसे लिक्विड नाइट्रोजन (LN2), सीमन, AI Gun तथा आवश्यक दवायें आदि भी उपलब्ध करवाई गईं। इस पैरावेट सेन्टर के माध्यम से दर्शन सिंह ने गाँव-गाँव में जाकर समुदाय के लोगों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाने संबंधी तथा पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी देनी प्रारंभ कर दी। वह इन गाँवों में जाकर अपना सम्पर्क नम्बर दे देते थे जिससे दूरस्थ गाँवों के लोग भी इनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के खुलने के कारण क्षेत्र में उन्नत नस्ल के स्वस्थ संकर पशु पैदा हो रहे हैं। दर्शन सिंह जी एक माह में 55 से 60 कृत्रिम गर्भाधान कार्य करते हैं। वह कृत्रिम गर्भाधान सेवा हेतु प्रति पशु ₹ 200.00 का शुल्क लेते हैं और माह में लगभग ₹ 11,000 तक की आय अर्जित करते हैं। वर्तमान समय में पशुपालन विभाग भी इनकी सहायता से गाँवों में अपनी पहुँच बना रहा है। श्री सिंह का पशुपालन विभाग के अधिकारियों से अच्छा समन्वयन है तथा वह आवश्यकतानुसार उनसे तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं।

तकनीकी ज्ञान : खुशहाली का विज्ञान

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की टिहरी इकाई ने वर्ष 2013-2014 में विकासखंड चंबा के 8 गांवों के कुल 8 अंगीकृत स्वयं सहायता समूहों के साथ उद्यानिकी विकास की गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। गुनियाठ ग्राम सभा के आस-पास के क्षेत्रों में अत्यधिक सब्जी उत्पादन किया जाता है अतः परियोजना ने ग्राम गुनियाठ के स्वयं सहायता समूह नामक समूह के साथ सब्जी उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया और समूह के 13 सदस्यों को आय सृजन हेतु सब्जी उत्पादन के लिये उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध करवाये।

इसी समूह के सदस्य वीर सिंह पूर्व से ही सब्जी उत्पादन करते थे। परियोजना के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने परियोजना से सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी ली। इनके समूह को टमाटर, बैंगन, बंदगोभी व फूलगोभी के उन्नत बीज उपलब्ध करवाये गये जिनको पौधशाला में उगाकर इन्होंने अन्य किसानों को भी निःशुल्क पौध वितरित की। पूर्व के वर्षों में सब्जी उत्पादन करके जहां लाभार्थी को ₹ 5000 से ₹ 8000 का मुनाफा होता था वहीं इस वर्ष परियोजना द्वारा प्राप्त जानकारी व उन्नत प्रजाति का बीज लगाकर उनका मुनाफा बढ़कर ₹ 15,000 से ₹ 20,000 प्रतिनाली तक बढ़ गया। पूर्व में पारंपरिक बीजों के द्वारा सब्जी उत्पादन से आमदनी और बीजों में रोग होने के कारण उत्पादन प्रभावित हो जाता था। इस वर्ष वीर सिंह ने ₹ 52,000 हजार रुपये से अधिक की सब्जी बेचकर ₹ 20,000 से ₹ 25,000 तक की शुद्ध आय प्राप्त की है। इस वर्ष टमाटर की फसल से इनको विशेष लाभ हुआ। इन्होंने टमाटर बेच कर प्रति कुंतल ₹ 32,000, बंदगोभी से प्रति कुंतल ₹ 6,000, फूलगोभी से प्रति कुंतल ₹ 8,000, बैंगन से प्रति कुंतल ₹ 3,500, लौकी से प्रति कुंतल ₹ 3,200 तक का व्यवसाय किया है।

आलू उत्पादन: आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिये आशा की किरण

परियोजना (ILSP) द्वारा उत्तरकाशी के 2013-14 के आपदाग्रस्त विकासखंड भटवाड़ी में चौरंगी सहकारिता डुंडा के माध्यम से आलू के संग्रहित विपणन की एक सार्थक पहल की गई। इस सहकारिता में 365 सदस्य हैं और सभी सदस्य महिलायें हैं। परियोजना द्वारा आलू के उत्पादन के लिये 2013-14 के दो आपदा प्रभावित गांवों निसमोर व सारी का चयन किया गया। आलू की प्रदर्शन गतिविधि से निसमोर गांव के 39 और सारी गांव के 24 परिवारों को आच्छादित किया गया। सदस्यों को 82 कुंतल आलू का कुफ्री ज्योति बीज ₹ 19 की दर से दिया गया। परियोजना द्वारा किसानों को सफल आलू उत्पादन के लिये बीज को एक पंक्ति में बोने, प्रत्येक अवस्था में फसल की सुरक्षा और कीटों से फसलों के बचाव आदि की जानकारी दी गई। सितम्बर 2014 में फसल तैयार होने के बाद सदस्यों को एक बार फिर कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग आदि की भी विस्तृत जानकारी दी गई। तैयार फसल से 11 कुंतल आलू उत्तरकाशी और 50 कुंतल आलू देहरादून की मंडियों में ₹ 18-24 के प्रचलित मंडी भाव पर भेजा गया। इस गतिविधि से चौरंगी सहकारिता को ₹ 19,800 का शुद्ध लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त मंड़ी कमीशन (₹1/किग्रा०) व सुगमीकरण शुल्क के रूप में (₹ 0.50/किग्रा०) ₹ 1650 का लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप किसानों को प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रति किग्रा० ₹ 5-6 का मुनाफा हुआ। धीरे-धीरे किसानों का मंडी के व्यवसायियों से संपर्क बढ़ रहा है और अब वे अपने उत्पाद सीधे मंडी को बेच सकते हैं।

स्वालंबन की ओर कार्यशाला का आयोजन

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला... स्वालंबन की ओर का आयोजन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के सभागार में दिनांक 09 जनवरी से 10 जनवरी को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के द्वारा किया गया। कार्यशाला का आयोजन परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह तथा फैडरेशनों के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने, उनके अनुभवों के आदान प्रदान, उनकी समस्याओं के निराकरण तथा भविष्य की रणनीति तय करने हेतु किया गया था।

कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त संसदीय सचिव श्री गणेश गोदियाल, विधायक श्री हरबंस कपूर एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्री एन०रविशंकर, श्री आ०एस० टोलिया, चेयरपर्सन, पब्लिक पॉलिसी, श्री आ०बी०एस० रावत, उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी गठन आयोग, डॉ० कमल सिंह, सी०ई०ओ०, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, डॉ० अविनाश आनंद, सी०ई०ओ०, वूल एवं शीप बोर्ड, मुख्य परियोजना निदेशक आई.एल०एस०पी० श्री विजय कुमार एवं परियोजना का स्टाफ आदि उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में 8 परियोजना जनपदों के 65 फैडरेशनों के 220 सदस्यों एवं प्रतिनिधियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यशाला में वक्ताओं द्वारा सहकारिताओं के सशक्तीकरण तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कई सुझाव दिये गये। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परियोजना द्वारा आई०एल०आर०टी० संस्था के माध्यम से विकसित करवाये गये सुशासन, विपणन तथा व्यावसायिक मॉडयूलों, केस अध्ययन पुस्तिका एक खामोश यात्रा तथा परियोजना की वेबसाइट www.ilsp.in का विधिवत विमोचन किया गया। इस अवसर पर परियोजना की सर्वाधिक टर्नओवर प्राप्त करने वाली सहकारिताओं द्वारा अपनी उपलब्धियों से संबंधित अनुभवों का आदान प्रदान किया गया तथा परियोजना के माध्यम से दिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप जिन अभ्यर्थियों ने रोजगार प्राप्त किये उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अनेकों प्रश्न पूछे गये जिनका निराकरण विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा किया गया। कार्यशाला में चेयर प्रोफेसर पब्लिक पॉलीसी दून यूनि० श्री आर०एस० टोलिया द्वारा समय-समय पर अत्यंत उपयोगी सुझाव दिये गये। उन्होंने प्रतिभागियों को कार्यशाला में प्राप्त अनुभवों एवं ज्ञान का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करने का आह्वान किया। कार्यशाला की विस्तृत जानकारी परियोजना की वेबसाइट www.ugvs.org, www.ilsp.in पर उपलब्ध हैं।

उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति एवं उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु अनुबंध

उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति - एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से उत्तराखंड के जनपदों में नस्ल सुधार कार्यक्रम/परियोजना के अंतर्गत 64 समन्वित पशु विकास केंद्रों की स्थापना (33 पुराने केंद्रों को तकनीकी सहयोग व 31 नये केंद्रों की स्थापना) के लिये दि० 24-9-2014 को परियोजना निदेशक ILSP, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी - उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के मध्य एक अनुबंध किया गया। उक्त अनुबंध के अंतर्गत बेरोजगार 64 नवयुवकों द्वारा (33 पूर्व से कार्यरत को सहयोग तथा 31 नये पैरावेट को रोजगार) पैरावेट के रूप में रोजगार प्राप्त किया जायेगा तथा 23,220 पशुपालकों के पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान, दवापान, टीकाकरण, बधियाकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधायें भी उपलब्ध करवाई जायेंगी। इस कार्यक्रम हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिये ₹ 2.45 करोड़ का वित्तीय सहयोग दिया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात आगामी पांच वर्षों में उन्नत नस्ल की भैंसों की संख्या 1356 और गायों की संख्या 1356 होने की संभावना है। वर्तमान में प्रति गाय 1.392 लीटर तथा प्रति भैंस 3.2 लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। परियोजना क्रियान्वयन के पश्चात उन्नत नस्ल की गाय से प्रति गाय 6.5 लीटर और उन्नत नस्ल की भैंस से प्रति भैंस 4-5 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होने की संभावना है। आगामी पांच वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 8600 लीटर की तथा दुग्ध विक्रय से होने वाली आय में ₹ 2,15000-00 (₹ 25 प्रति लीटर की दर से) तक की संभावित वृद्धि होगी।

प्रगति स्वायत्त सहकारिता, मोतियापाथर का सराहनीय कदम

प्रगति स्वायत्त सहकारिता, मोतियापाथर, अल्मोड़ा द्वारा माह नवंबर में ₹ 10 लाख मूल्य का 205 कुंतल आलू का प्रमाणीकृत एवं शोधित कुफ्री ज्योति बीज, लाहौल स्पीति आलू उत्पादक संघ (LSPGA) कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश से खरीद कर सहकारिता के सदस्यों तथा आस-पास के किसानों व फैडरेशनों को उचित समय पर उपलब्ध करवाया गया। इसके लिये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने वित्तीय व्यवस्था समूह की CCL एवं इंटरलोनिंग के माध्यम से की जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस गतिविधि से सहकारिता को रेखीय विभागों व समुदाय में काफी पहचान व सराहना मिली है क्योंकि पूर्व में रेखीय विभाग सहकारिता को पहाड़ी क्षेत्र हेतु उपयुक्त बीज समय पर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे।

जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कृषक-वैज्ञानिक संवाद

दिनांकः 11/09/2014 को एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना इकाई बागेश्वर के तत्वाधान में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा से आये वैज्ञानिकों द्वारा केन्द्र सरकार की जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत आगामी रबी की विभिन्न फसलों के प्रदर्शन व तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कृषक-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभागीय परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना व जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत कृषकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, कृषि निवेश तथा जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में उपस्थित लाभार्थियों को जानकारी दी गई।

नेचर फेस्टीवल में सहकारिताओं के उत्पादों को मिली सराहना

दिनांक 01 नवम्बर से 2 नवम्बर तक, राजपुर रोड देहरादून में आयोजित मेले में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की अल्मोड़ा इकाई की सहकारिताओं द्वारा अपने-अपने ग्रामीण उत्पादों जैसे मसाले, पहाड़ी दालें, लकड़ी से बना सजावटी सामान एवं हाथ से बने ऊनी सामान जैसे स्वेटर, शॉल, स्टोल आदि सामग्री को बिक्री हेतु रखा गया। इन उत्पादों की बिक्री से सहकारिता को कुल मिलाकर ₹ 5,789 की आय हुई।

परियोजना की चमोली ईकाई द्वारा राज्यस्तरीय गौचर मेले (14 से 20 नवम्बर, 2014) में प्रतिभाग

जनपद चमोली के अन्तर्गत आने वाली 9 नोडल सहकारिताओं एवं नए चयनित विकास खण्ड थराली से लगभग 210 प्रतिभागियों, समूह सदस्यों तथा कर्मचारियों द्वारा सुप्रसिद्ध गौचर मेले में शैक्षिक भ्रमण किया गया। इस शैक्षिक भ्रमण से सदस्यों को कृषि संबंधित जानकारियों के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन, जलवायु परिवर्तन, वन प्रबन्धन, आपदा राहत, वैज्ञानिक प्रगति, नये एवं उन्नत बीज, कृषि औजार, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, उद्यानिकी आदि की जानकारी प्राप्त हुई। चमोली जनपद की चार सहकारिताओं द्वारा स्थानीय उत्पादों का विपणन करके ₹18,544 का व्यापार किया गया।

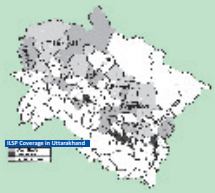

प्रभागीय परियोजना प्रबनधन इकाई सम्पर्क पताः

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
टेलीफैक्सः 05962-230910, 230305
ईमेलः dpmalmora@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
टेलीफैक्सः 05963-221502, 211746
ईमेलः dpmbageshwar@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
टेलीफैक्सः 01372-251355, 251451
ईमेलः dpmchamoli@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
टेलीफैक्सः 01376-256133, 256249
ईमेलः dpmtehri@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
टेलीफैक्सः 01373-223925, 223466
ईमेलः dpmuttarkashi@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रूद्रप्रयाग
ईमेलः dpmrudraprayag@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
ईमेलः dpmpithoragarh@ugvs.org
(05964) 223025

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
ईमेलः dpmdehradun@ugvs.org

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। ग्रामीण परिवारों को चिरन्तर आजीविका का अवसर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाते हुये, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति जानी है।

परियोजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक कुल सात वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुआ है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के 11 जनपदों के 41 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

प्रकाशकः श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक, UGVS

संपादकीय टीमः परियोजना स्टाफ

पताः
216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून
टेलीफैक्सः 0135-2774800, 2773800
ईमेलः info@ugvs.org
वेबसाईटः www.ugvs.org

केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

डेरी एवं सब्जी उत्पादन हेतु जनपद चमोली की सहकारिताओं का शैक्षिक भ्रमण

परियोजना द्वारा सहकारिताओं के सदस्यों हेतु समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण आयेजित किये जाते हैं ताकि सदस्यों की जानकारियों में वृद्धि हो सके तथा इन जानकारियों का समावेश वे अपनी गतिविधियों में कर सकें। परियोजना की चमोली इकाई द्वारा दिनांक 6 नवम्बर से 10 नवम्बर 2014 तक सहकारिता से जुड़े समूहों के लिये ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून एवं आस पास के स्थानों की मंडियों तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के गोपालक समूहों की डेयरियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण का मूल उद्देश्य परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सहकारिताओं एवं नये चुने गये विकासखंडों के समूहों को डेयरी एवं सब्जी उत्पादन की बेस्ट प्रैक्टिसेज के साथ-साथ बड़े स्तर पर मंडी में विपणन कार्य की जानकारी प्राप्त करना था। इस भ्रमण में 42 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभागियों को इस भ्रमण से डेरी के अंतर्गत निम्न जानकारियां प्राप्त हुईः-

डेरी के अंतर्गत सदस्यों द्वारा गाय/भैसों की नई एवं उन्नत प्रजातियों उन्नत गौ वंश पालन से लाभ तथा विभिन्न नस्लों, पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन हेतु साहीवाल, रेड सिन्धी, थारपारकर, हरियाणा आदि उपयोगी प्रजातियों की, पशुओं के आवास हेतु उचित स्थान के चयन, स्वच्छ जल की व्यवस्था, अच्छे प्रजनन हेतु कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सम्पूर्ण जानकारी तथा गोपशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों एवं उनके प्राथमिक उपचार की समस्त जानकारी प्राप्त की गई।

इसी प्रकार से सब्जी उत्पादन के अंतर्गत सदस्यों द्वारा सब्जी उत्पादन एवं विपणन हेतु विभिन्न मंडियों में लायी जाने वाली सब्जियों, फलों, अनाजों आदि के मूल्य, मंडी व्यवस्था, विपणन एवं मौसमी तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन हेतु प्रारम्भ से विपणन तक की प्रक्रिया की आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

इस प्रकार के सफल मॉडलों के शैक्षिक भ्रमणों के आयोजन से सदस्य उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज के माध्यम से तथा एक दूसरे से सूचनाओं एवं अपने अनुभवों का आदान प्रदान करके अपनी जानकारियों में वृद्धि तथा समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।

परियोजना की दिसंबर 2014 तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति का क्रियान्वयन राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित विकासखंडों में किया जा रहा है। जुलाई 2013 से परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परियोजना की दिसंबर 2014 तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैः-

- 5 जनपदों के 17 विकासखंडों के 3455 स्वयं सहायता समूहों को आच्छादित तथा 72 फैडरेशनों का गठन करते हुये, 975 गांवों में 3495 शेयरधारकों को व्यावसायिक कार्यों हेतु ₹ 1.23 करोड़ की धनराशि का वित्तीय सहयोग दिया गया है।
- इन 72 फैडरेशनों द्वारा ₹ 8.37 करोड़ का टर्नओवर और ₹ 0.60 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया है।
- 8 जनपदों में 4555 नये परिवार, 15 नये विकासखंड और 183 गांवों को चिन्हित किया गया है।
- 8 जनपदों में 15 नये विकासखंडों के 156 गांवों में 3608 परिवारों के साथ 455 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण- परियोजना का लक्ष्य इस पाठ्यक्रम में 15,000 छात्रों को कौशल प्रदाता सहभागियों के माध्यम से कौशल प्रदान करना है। दिसम्बर 2014 तक इस कार्य हेतु 679 छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश दिलाया जा चुका है। इन छात्रों में 241 लड़के एवं 438 लड़कियां हैं। इनमें से 384 गरीबी रेखा से ऊपर और 384 गरीबी रेखा से नीचे के हैं। अब तक 452 छात्रों को प्रशिक्षण, 233 को प्लेसमेंट प्रस्ताव तथा 134 को रोजगार दिलाया जा चुका है।
- अल्मोड़ा तथा टिहरी जनपदों में 8 संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- भटवाड़ी (उत्तरकाशी) के लाटा गांव में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के साथ चारा पार्क का पाइलट तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत 5 हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन हेतु 40 परिवारों का आच्छादन किया जाना है।
- परियोजना क्षेत्र में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड (ULDB) के साथ 64 एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों (ILDC) (33 पुराने केंद्रों को तकनीकी सहयोग व 31 नये केंद्रों की स्थापना) की स्थापना एवं संबद्ध सेवाओं हेतु परियोजना द्वारा सहयोग किया गया है।
- परियोजना द्वारा कुल मिलाकर अब तक ₹ 32.98 करोड़ की वित्तीय प्रगति की गई है।
- परियोजना की प्रगति के नियोजन एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये MIS विकसित किया गया है तथा ज्ञान प्रबंधन के संसाधन केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को उपयोगी जानकारी वॉयस और टैक्स्ट मैसेजेज के रूप में भेजी जा रही है।

मुद्रण : **एलाईड प्रिन्टर्स,** देहरादून 0135-2654505